POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जून, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। पूरे देश में इस समय भारत की अध्यक्षता को लेकर उत्साह है। इसी सन्दर्भ में 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' एक अत्यंत उपयोगी मंत्र है, जो हमें विश्व कल्याण की ओर ले जा सकता है।

लेकिन यदि जी-20 के एजेंडे का अवलोकन किया जाए तो पता चलेगा कि 'उपभोक्ता कल्याण' के मुद्दे को करीब-करीब दरकिनार सा कर दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता दिए बिना जी-20 एजेंडा सम्पूर्ण नहीं होगा। इस वर्ष जी-20 बैठक के लिए भारत का लक्ष्य सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान खोजना और 'वैश्वीकरण को जन-साधारण के लिए कारगर बनाना' है।

विश्व के नेता अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से आर्थिक और विकास की प्राथमिकताओं और समकालीन वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

मेरा मानना है कि उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि जी-20 की बैठकों में भारत की ओर से आर्थिक इंजन की धुरी 'उपभोक्ता' पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि वर्ष 1999 में स्थापना से लेकर वर्ष 2007 तक जी-20 ने कभी भी उपभोक्ता संरक्षण को महत्व नहीं दिया। लेकिन, वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण धीरे-धीरे जी-20 के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया।

वर्ष 2008 से 2022 तक जी-20 ने सदैव सदस्य देशों को उपभोक्ता संरक्षण को केंद्र में रखने, नीतियों को मजबूत करने, प्रभावी प्रवर्तन तंत्र विकसित करने एवं उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भारत को अगली बैठकों में उपभोक्ता संरक्षण को खास अहमियत देनी चाहिए। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-20 को जन-आंदोलन बनाने के प्रेरणादायी अभियान को बल मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण को प्राथमिकता देने से स्थाई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और वैश्विक मुद्दों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।

जी-20 के प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण को उच्च प्राथमिता देकर भारत एक नई आवाज मुखर कर सकता है। इससे भारत के बाद ब्राजील (2024) एवं दक्षिण अफ्रीका (2025) जी-20 के एजेंडे में उपभोक्ता संरक्षण को केंद्र में रख कर प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं।

टीवी-एसी, फ्रिज की रिपेयरिंग से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगी कंपनियां

ज्यादातर कंपनियां अपने उत्पाद बेचते समय लंबे-चौड़े वादे करती हैं। वो गारंटी और वारंटी के साथ सामान तो बेच देती हैं, लेकिन बाद में खराबी आने पर मरम्मत को लेकर आनाकानी करती हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद समय से पहले खराब होने पर उपभोक्ताओं को लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। लेकिन कई मामलों में कंपनियां किसी न किसी बहाने बिना शुल्क मरम्मत करने से बचती हैं, या फिर रिपेयरिंग के लिए अलग से फीस या सर्विस चार्ज भी देने के लिए कहा जाता है।

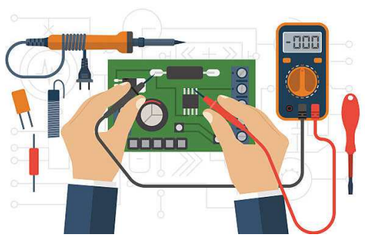

केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं को नया अधिकार दिया है। जिसके तहत मोबाइल, टैबलेट जैसे गैजेट, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, भारी कृषि मशीनरी की लाइफ तय होगी। कंपनी को उपभोक्ता को उसके रखरखाव और रिपेयर की पूरी जानकारी देनी होगी। खराब होने पर संबंधित पुर्जा ही बदलने की जरूरत होगी, लेकिन कोई नया सामान बेचने की आड़ में कंपनियां ग्राहकों को झांसा नहीं दे पाएंगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के विभाग ने इसके लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल भी शुरू किया है। खबरों के मुताबिक उपभोक्ताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए और तमाम झंझटों से मुक्ति के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल में दी गई जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं की मदद के लिए इसमें एलजी, ओप्पो केयर, बोट, हैवेल्स, एचपी, केंट, सैमसंग और होंडा मोटर्स जैसे ब्रांड को जोड़ा गया है। इस पोर्टल पर उत्पादों से जुड़ी मरम्मत व अन्य शिकायतों के लिए मदद मिल पाएगी।

मुफ्त दवा में हम पहले पायदान पर

सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में देश में राजस्थान पहले पायदान पर है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 76.02 फीसदी मरीजों को मुफ्त दवा मिल रही है। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर तेलंगाना राज्य है।

यह खुलासा राज्यों के दवाओं की उपलब्धता की सॉफ्टवेयर के जरिए मॉनिटरिंग करने वाले केंद्र सरकार के ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) की अप्रैल 2023 की रिपोर्ट में हुआ है। अक्टूबर 2011 से संचालित नि:शुल्क दवा योजना में बजट 195 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 14 करोड़ मरीज लाभान्वित हुए।

हाड़ौती में तैयार की सेब की फसल

कोटा में बालिता गांव के किसान राजेंद्र मीना अपनी 3 एकड़ जमीन पर पारंपरिक खेती से हटकर कई नवाचार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी जमीन पर सेब का बागान लगाया है। अभी फल आने लगे हैं। एक पेड़ पर 70-80 तक फल लगे हैं। इनका आकार भी अच्छा है।

खास यह है कि सेब ठंड़ी जलवायु में होते हैं, लेकिन हाड़ौती की गर्म जलवायु में भी उनके प्रयास रंग ला रहे हैं। इस महीने में फल बिकने लायक हो जाएंगे। इनके भाव भी अच्छे मिलने की उम्मीद है। क्योंकि, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं। इनमें रसायनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। सेब के पौधे कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में रोपे गए थे । राजेंद्र मीना अपने खेत में गेहूं, अनार, मौसमी और नींबू की भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उनके अधिकांश उत्पाद खेत में ही बिक जाते हैं।

बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की समस्या

देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.83 फीसदी पर पहुंच गई इससे पहले मार्च में ये 7.60 फीसदी पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 9.22 फीसदी और ग्रामीण बेरोजगारी की दर 7.18 फीसदी रही। यानी बेरोजगारी गांवों से ज्यादा शहरों में बढ़ी।

रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और राजस्थान में दर्ज की गई है। हरियाणा में यह 34.5 फीसदी और राजस्थान में 28.8 फीसदी है। जबकि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में सबसे कम बेरोजगारी देखी गई।

खुले में शौच से 50 फीसदी गांव मुक्त

देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ साल पहले खुले में शौच से मुक्ति मिशन शुरू किया था। देश के आधे से ज्यादा गांवों ने मिशन के तहत दूसरे चरण में खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल कर लिया है।

मंत्रालय के अनुसार, अब तक 2.96 लाख से ज्यादा गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। यह 2024-25 तक मिशन के दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अहम कदम है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर भी जागरूकता आई है। एक लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है।

चिरंजीवी बीमा में 25 लाख का वादा...

भले ही चिरंजीवी में बीमा 25 लाख रुपए सालाना का हो, लेकिन इलाज के लिए रोजाना 6 हजार रुपए तक खर्च का पैकेज गंभीर रोगियों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। इसमें दवाइयां जांच आदि सब खर्च सम्मिलित है। इससे गंभीर मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा।

सच यह है, गंभीर बीमार मरीज की जान बचाने के लिए पहले ही दिन 15 से 20 हजार का खर्चा होना एक सामान्य बात है। ऐसे में निजी अस्पताल 6 हजार रुपए के बाद इलाज करना ही बंद कर देते हैं। परिजन भी चिरंजीवी में होने के कारण ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते। ऐसे में निजी अस्पताल परिजनों को सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने की सलाह देते हैं। क्योंकि निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के अनुसार पैकेज में जटिलता के इलाज की अलग से व्यवस्था ही नहीं की गई है।

मनरेगा में नहीं मिला पूरा रोजगार

मनरेगा में सरकार ने गारंटी तो 100 दिन के रोजगार की दी है, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में औसतन 43 दिन ही रोजगार मिल रहा है। 54 लाख से ज्यादा परिवारों में से 100 दिन रोजगार सिर्फ 1.42 लाख परिवारों को ही मिला। 53 लाख परिवारों को 57 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा।

पंचायतीराज विभाग की चार साल की दिसंबर तक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की घोषणा की है। मनरेगा में 2021-22 में खर्च 10464 करोड़ रुपए था, इस साल यह 6878 करोड़ रुपए रहा। यानी पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत तक कम है।

बीच में पढ़ाई छोड़ रही बेटियां

प्रदेश में करीब तीन फीसदी बेटियां स्कूल से दूर हैं। ग्रामीण इलाकों में बेटियां स्कूल में प्रवेश तो ले रही हैं मगर किशोरावस्था तक आते-आते स्कूल छोड़ रही हैं। 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बेटियों का आंकड़ा देखें तो राजस्थान देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे फिसड्डी राज्य है।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (असर) 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 11 से 14 वर्ष की 2.9 फीसदी बालिकाएं स्कूल नहीं जा रही हैं। वहीं 15-16 आयुवर्ग की 9.4 फीसदी बालिकाएं स्कूल से दूर हैं।

इसका मुख्य कारण कई ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का दूर होना, स्कूलों में पर्याप्त शौचालय नहीं होना और शिक्षकों की कमी मानी जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अभी भी शिक्षकों के 60-65 हजार पद खाली हैं।

भारत बना सबसे बड़ी आबादी वाला देश

दुनिया की आबादी अब 800 करोड़ के पार हो चुकी है। हर 5वें व्यक्ति में एक भारतीय है। क्योंकि भारत 142.86 करोड़ लोगों के साथ पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। चीन के 142.57 करोड़ के मुकाबले हमारी जनसंख्या 29 लाख ज्यादा है।

यूनाइटेड नेशंस पापुलेशन फंड (यूएनएफपीए) द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट -23 में यह आंकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2022 में चीन की आबादी में 8.5 लाख की कमी आई है। 1961 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है।

गांवों में शिक्षा के प्रति मची अनूठी होड़

प्रदेश के जालौर जिले के गांवों में बेहतरीन स्कूल भवन बनवाकर सरकार को देने की होड़ चल रही है। यहां गांवों में बड़ी संख्या में प्रवासी है। वे अपने गांव में करोड़ों रुपए की लागत के स्कूल भवन बनवाकर सरकार को भेंट कर रहे हैं। अगर किसी गांव में कोई बड़ा सेठ नहीं है तो गांव के कई लोग मिलकर भी स्कूल का भवन बनवा रहे हैं।

इस अनूठी होड़ से गांवों के बच्चों और शिक्षकों को आधुनिक सुविधा वाले बेहतरीन स्कूल भवन मिल रहे हैं। यहां स्कूल बनवाने वाले निर्धारित लागत से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है कि गांव का स्कूल सर्वश्रेष्ठ हो। जिले के कई गांवों में ऐसे स्कूल भवन बन चुके हैं।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

जैसा कि विदित है ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इसी क्रम में इस साल 'राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं कितनी लाभकारी' विषय पर प्रविष्ठियाँ आमन्त्रित की गई। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से बीकानेर जिले के पत्रकार बृजमोहन आचार्य को वर्ष 2022 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

बृजमोहन आचार्य पुत्र नंदकिशोर आचार्य बीकानेर जिले के मूल निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के बीकानेर संस्करण से जुड़े हैं।आचार्य को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

महंगा पड़ा डाकघर को पीपीएफ पर ब्याज रोकना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-3 में कुलदीप कुमार गुप्ता ने शास्त्रीनगर स्थित पोस्ट ऑफिस (डाक विभाग) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने परिवाद में बताया कि अगस्त, 2004 में उसने और उसके पिता ने एचयूएफ (हिंदू अविभाज्य परिवार) की हैसियत से शास्त्री नगर पोस्ट ऑफिस में दो पीपीएफ खाते खुलाए थे। पोस्ट ऑफिस ने पीपीएफ खाते की 15 साल की अवधि पूरी होने पर उसके पिता के खाते का भुगतान कर दिया। लेकिन पोस्ट ऑफिस ने मेरे (परिवादी) खाते में दिया ब्याज रिकवर करने के आदेश दे दिए। जबकि उन्होंने एचयूएफ के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं छुपाई है। कानूनन रूप से बेटा, छोटी एचयूएफ का सृजन कर सकता है। ऐसे में उसे ब्याज सहित राशि दिलाई जाए।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने खाताधारक को दो एचयूएफ (हिंदू अविभाज्य परिवार) का सदस्य बताकर उसके पीपीएफ खाते का ब्याज रोकने को सेवा दोष माना। आयोग ने डाक विभाग पर 1.25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही पीपीएफ खाते की ब्याज राशि 31 मार्च, 2020 से नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कदम' जयपुर